International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 4, April- 2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

भारत चीन सम्बन्धः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (1947–2010 ई०)

डॉ० राजकुमार

सहायक प्रोफेसर

राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय साहा, अम्बाला

भूमिका :

पाकिस्तान के बाद चीन भारत की उत्तर दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण पड़ौसी राज्य है जिसके साथ भारत में महत्त्वपूर्ण विदेशी सम्बन्ध है । जहां तक पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में विरासत की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है वही चीन के साथ भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के समय की विरासत को भूलाकर नए सिरे से सम्बन्ध स्थापित किए हैं । इन नए सम्बन्धों का आधार नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के दोनों की भूमिकाओं के आकलन पर आधारित रहा है । ऐतिहासिक रूप से भारत व चीन की दो प्रमुख सभ्यताएँ रही हैं जो अपासी सह–अस्तित्व के आधार पर स्थापित थी क्योंकि चीन तथा भारत दोनों ही साम्राज्यवाद के हाथों उत्पीड़ित थे । भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया तथा साम्यवादी चीन 1949 ई० में गणतन्त्र बन गया । नेहरु को आशा थी कि दोनों देश जो साम्राज्यवादी शक्तियों से उत्पीड़ित थे तथा जिनकी निर्धनता तथा कम विकास की समस्याएँ एक जैसी थी । दोनों देश निष्पक्षता तथा अनाक्रमण की नीतियों के समर्थक थे । दोनों के मधुर सम्बन्ध बने भी तथा मित्रता की पराकाष्ठा स्वरूप ''चीनी हिन्दी भाई–भाई'' के स्वर्णिम युग की स्थापना में बले । लेकिन शीघ्र ही दोनों देशों के बीच युद्ध की विभीषका भी प्रज्ज्वलित हुई तथा दोनों देश एक लम्बे अन्तराल तक सम्बन्धरहित स्थिति में रहे । इसके बाद सम्बन्धों में सुधार हुआ और यह प्रक्रिया आज भी जारी है । दोनों देशों के सम्बन्ध सहयोग–संघर्ष सहयोग के दौर से गुजरे ।

भारत चीन सम्बन्धों का वर्णन पांच चरणों में किया जा सकता है:–

(1) स्वर्णिम युग (1949–1959 ई०) (2) संघर्ष का काल (1959–62) (3) संबंध रहितता काल (1962–76) (4) वार्तालाप का काल (1976–88) (5) मधुर सम्बन्धों की पुनः शुरूआत (1988–2010 ई०)

स्वर्णिम युग (1949–1959 ई०)

भारत चीन सम्बन्धों का प्रथम दशक मैत्रीपूर्ण रहा । सर्वप्रथम भारत ने एक प्रजातान्त्रिक देश होते हुए अपने पड़ौस में 1 अक्तूबर 1949 को चीन को साम्यवादी गणतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी । अमेरिका के विरोध के बावजूद भी भारत ने चीन को हर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्थान दिलाने का प्रयास किया । जिसका मुख्य उद्देश्य शायद दोनों के बीच स्थापित परस्पर लाभकारी संबंधों के माध्यम से ये एक महान व अविजित शक्ति बनना चाहते थे ।

भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी चीन का समर्थन किया जिसमें फरवरी 1951 ई० में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरिया के युद्ध के संदर्भ में चीन को अक्रान्ता घोषित करने के प्रस्ताव का भारत ने विशेष कर चीन की नीतियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया । इसके साथ–साथ सितम्बर 1951 में सनफ्रांसिसको में हो रहे सम्मलेन में भारत ने जापान के साथ शांति सन्धि की घोषणा पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि चीन को इस संधि में शामिल नहीं किया गया था । भारत का मानना था कि सुदुरपूर्व में चीन की भागीदारी के बिना शान्ति प्रयास निरर्थक रहेंगे । चीन ने भी भारत की नीतियों में विश्वास जताया और मित्रता बढ़ी ।

पंचशील तथा तिब्बत समझौता :

दोनों देशों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध अपने पूर्ण चरमोत्कर्ष पर 29 अप्रैल 1954 को पहुंचे जब भारत व चीन के मध्य तिब्बत के सन्दर्भ में व्यापार व आपसी आदान-प्रदान के एक 8 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए । इस समझौते से भारत ने ब्रिटिश सरकार द्वारा तिब्बत में उपभोगिता सीमा अधिकारों को त्यागा तथा तिब्बत को चीन का क्षेत्र माना। इस समझौते द्वारा चीन तथा भारत दोनों ने अपने सम्बन्धों में पांच सिद्धान्तों को मानने का प्रण लिया । ये सिद्धान्त पंचशील समझौते की प्रस्तावना में लिखे गए थे । प्रथम एक-दूसरे देश की सीमाओं एवं प्रभुसत्ता की आपसी स्वीकृति । द्वितीय एक दूसरे के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, तृतीय एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना । चतुर्थ समानता तथा आपसी हितों की रक्षा करना । पंचम शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व। चीन ने भारत की प्रभुसत्ता और इसकी सीमाओं के प्रति आदर दर्शाने का गम्भीर वचन दिया जिससे दोनों देशों में परस्पर सहयोग के नये युग की शुरूआत हुई । भारत द्वारा तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लेने पर दोनों देशों के सम्बन्ध सुदृढ़ हुए । जून 1954 ई० में चीन के प्रधानमंत्री ''चाऊ इन लाई'' ने भारत की यात्रा की और उनका हार्दिक स्वागत किया । यात्रा के अन्त में दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने सांझे ब्यान में पंचशील में आस्था व्यक्त की ।

4. हिन्दी चीनी भाई-भाई की भावना (1954-56):

भारत चीन सम्बन्धों का यह प्रमोद का काल था । जब दोनों देशों में हिन्दी-चीनी भाई-भाई जैसे नारों की गूंज थी । उसी वर्ष बाद में नेहरु की चीन यात्रा अप्रैल 1955 की बांडुग कान्फ्रैंस में दोनों देशों के बीच निकटतम सहयोग तथा नवम्बर-दिसम्बर 1956 ई० में चाऊ इन लाई की भारत में दूसरी यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार आया । 1 अप्रैल 1955 ई० को ल्हासा आलेख पर हस्ताक्षर, तायवान समस्या पर भारत का चीन को पूर्ण समर्थन का आवश्वासन तथा संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रवेश के अधिकार को प्राप्त करने के लिए चीन को भारत का सहयोग । इन सबसे चीन बहुत प्रसन्न हुआ । चीन के बदले में गोवा के मामले पर भारत को समर्थन दिया । भारत तथा चीन दोनों ने सीटों (म।ज्ब) का विरोध किया ।

5. भारत तथा चीन के बीच मानचित्रों पर मतभेद :

हालांकि इस दौरान दोनों देशों में सभी बातें ठीक-ठाक भी नहीं थीं। 1954 ई० में चीन में छपे हुए कुछ मानचित्रों में बहुत बड़े भारतीय क्षेत्र को चीन का भाग दिखाया गया जिसकी प्रतिक्रिया जवाहर लाल नेहरु ने की और चीन प्रधानमंत्री ने नेहरु को पुराने मानचित्र की बात कहकर टाल दिया । लेकिन चीन ने बाराहोती में अपना शिविर स्थापित कर लिया । भारत ने अपना विरोध पत्र चीनी प्रधानमंत्री को दिया जिसमें कहा गया कि सीमा संबंधी कोई मतभेद नहीं है । इसे मित्रतापूर्वक ढंग से निपटा लिया जायेगा।

6. नेफा (छम्थ।) में चीनी घुसपैठ :

सितम्बर 1958 ई० में चीनी सैनिकों ने नेफा के लोहित मण्डल में घुसपैठ की और बाद में तिब्बत सीमा के साथ लैपथल सांगचोमाला में भी सैनिक चौकियां स्थापित कर लीं ।

7. सीमा विवाद उत्पन्न होना :

1957-58 में भारत तथा चीन के सम्बन्धों में तनाव आ गए तथा भारत चीन के बीच सीमा विवाद उत्पन्न हो गया । इस प्रकार चीन का भारतीय सीमा पर दावा बड़ा चौकानें वाला था । सितम्बर 1958 में नेहरु ने चीनी प्रधानमंत्री को चीन के भारतीय सीमा पर दावे को कठोरता से नकारने के विरोध में पत्र लिखा जिसमें चीनी प्रधानमंत्री ने 23.1.1959 को भारत-चीन सीमा कभी भी औपचारिक रूप से सीमांकित नहीं की गई के बारे उत्तर भेजा । जिससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय सीमाओं के प्रति चीनियों के इरादे नकारात्मक थे ।

इस प्रकार 1949–59 ई० के वर्षों में भारत–चीन सम्बन्ध आरम्भ में सकारात्मक तथा बाद में नकारात्मक दिखाई दिए ।

संघर्ष का काल (1959–1962 ई०):

1959 ई० में भारत चीन सम्बन्धों में अधिक कटुता तब आई जब तिब्बतियों के विद्रोह के परिणामस्वरूप तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा ने, जिसका हिन्दू आदर करते थे । चीनी व्यवहार से दुखी होकर, तिब्बत से भागकर भारत में शरण ली । अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग ने भी यह निर्णय दिया कि चीनी दलाई लामा के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे । भारतीय सरकार ने दलाईलामा को शरण दी परन्तु भारत में तिब्बत की प्रवासी सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी । चीनी अधिकारियों ने दलाई लामा को शरण देने पर आपत्ति जताई और बदले में लद्दाख में कोंग का दर्रे में अपने सैनिक भेज दिए और लगभग 12 भारतीय सैनिक मार दिए। जब भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया तो चीन ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया ।

चीन आक्रमण 1962 ई०:

नेहरु का एशिया का नेता बनने का सपना उस समय टूट गया जब चीन ने छम्थ। (छवतजी म्ेंजमतद थ्तवदजपमत ।तमं) नेफा (आधुनिक अरुणाचल प्रदेश) पर भारी पैमाने पर आक्रमण कर दिया और कई भारतीय चौकियां रौंद डाली । भारतीय क्षेत्रीय कमाण्डर भयभीत होकर पीछे हट गये और अब चीनियों के लिए भारत के मार्ग खुले थे । समस्त भारत में भय का यह वातावरण पैदा हो गया कि चीन असम पर अधिकार कर लेगा । 9 नवम्बर 1962 ई० को भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति कनैडी को पत्र लिखकर भारत चीन सीमा पर स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक बताकर सैनिक सहायता की मांग की तथा इसी प्रकार इंग्लैंड की सरकार से भी सैनिक सहायता मांगी । चीन ने पश्चिमी शक्तियों के डर से भारत की सीमा पर अग्रिम क्षेत्रों से अपनी सेवाएँ हटा लीं तथा स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही है और आज 51 वर्ष बाद भारत चीन सीमा को रेखांकित नहीं किया गया है ।

संबंध रहितता का काल 1962–1976 ई०

दोनों देशों के मध्य संबंधों का तीसरा चरण 15 वर्षों का था । संबंध रहितता का काल था । यद्यपि देशों ने अपने राजनयिक सम्बन्ध तो समाप्त नहीं किए परन्तु अपने–अपने राजदूतों को अवश्य वापिस बुला लिया। इसके साथ–साथ चीन पाकिस्तान के बढ़ते सम्बन्धों के कारण भी दोनों देशों में संकट बढ़ गया । चीन ने भारत पाक संबंधों की कटुता का लाभ उठाते हुए 1963 में पाकिस्तान के साथ समझौता करके पाक अधिकृत कश्मीर (च्ज्ञ) का लगभग 5180 वर्ग कि०मी० का क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया और भारत के कड़े रूख के बाद भी चीन ने अपना कार्य जारी रखा । 1970 ई० के दशक में जब पाक–अमेरिका–चीन धुरी स्थापित हो गयी जिसका मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के साथ भारत परिरोधन करना था, से भी स्थिति गम्भीर हो गयी । इसी कारण से चीन संयुक्त राष्ट्र का स्थाई सदस्य बना व पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया लेकिन 1974 ई० में भारत ने परमाणु परीक्षण व 1975 में सिक्किम को अपने क्षेत्र में मिलाया जिससे मतभेद और उभरे । परन्तु शीघ्र ही चीनियों का भारत आने का रास्ता खुल गया । अन्ततः अप्रैल 1976 ई० में के०आर० नारायणन को भारत ने 15 वर्षों के बाद अपना राजदूत नियुक्त कर दिया । कुछ दिनों बाद चीन ने भी ऐसा ही किया । अतः दोनों के बीच संबंध रहितता के युग की समाप्ति हो गयी और फिर राजनीतिक सम्बन्धों का सूत्रपात हो गया ।

वार्तालाप का काल 1976–1988 ई०:

1976 से 1988 तक के काल को दोनों देशों के मध्य नई शुरूआत का युग कहा जा सकता है । इस युग में दोनों देशों में नीति निर्माताओं में बदलाव आया । 1976 ई० में माओ–त्से–तुंग की मृत्यु से रुढ़िवादी युग की समाप्ति हो गयी । इसके स्थान पर नया नेतृत्व डेंग

हसाओ पिंग द्वारा सम्भाला गया जिससे चीन में उदारीकृत विश्व व्यवस्था के प्रति आस्था व्यक्त की । इस समय जनता दल के भारतीय विदेशी मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन यात्रा की लेकिन वियतनाम पर चीन द्वारा आक्रमण करने के कारण यह यात्रा सफल न हो पायी परन्तु फिर भी दोनों देशों के लिए यह यात्रा सकारात्मक रही । यह समय दोनों देशों के लिए मधुर सम्बन्धों का रहा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में परिवर्तन चीन–अमेरिका संबंधों से हुआ था परन्तु धीरे–धीरे इनके संबंधों में तनाव बढ़ता गया । भारत व अमेरिका के संबंध तो पहले से ही कटु चल रहे थे जिससे धीरे–धीरे दोनों देशों एक दूसरे से नजदीक आ गए । इसके साथ–साथ दोनों देशों ने गुटनिरपेक्षता की बात की । कुछ दिनों बाद जून 1980 ई० में डेंग हसासो पिंग ने 1960 के चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई का चीन भारत सीमा विवाद सुलझाने का प्रस्ताव दोहराया जिसके अन्तर्गत नियंत्रण देखा पर शान्ति स्थापित करने की बात कही गयी । बाद में 1983 ई० में लोकसभा में भारतीय विदेशमंत्री द्वारा सीमा विवाद सुलझाने हेतु संपुटित प्रस्ताव को चीन के पेशकश का जिक्र किया जिससे साफ होने लगा कि दोनों देश अपने विवादों को हल करने के इच्छुक हैं । 1981 से 1987 तक दोनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 8 महत्त्वपूर्ण दौर दोनों देशों की राजधानियों में सम्पन्न हुए । दुर्भाग्यवश दोनों देशों के बीच सीमा विवाद न सुलझ सका परन्तु आवश्यक मुद्दों को सुलझाने का मार्ग अवश्य ही प्रशस्त हुआ । इस प्रकार 1986 से 1988 का काल दोनों देशों के बीच भविष्य के प्रगाढ़ सम्बन्धों की स्थापना हेतु अति महत्त्वपूर्ण युग था।

5. सहयोगात्मक सम्बन्धों का युग 1988–2010 तक :

इस दौरान दोनों देशों में सहयोगात्मक संबंधों का युग एक महत्त्वपूर्ण युग था । इस काल में दोनों देशें के मध्य सम्बन्धों के सर्वांगीण विकास करने का फैसला किया गया तथा दोनों ही देशों ने यथार्थवाद का परिचय देते हुए बड़े ही परिपक्व ढंग से सम्बन्धों की कड़ी को आगे बढ़ाया ।

दिसम्बर 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा, दोनों देशों के लिए सकारात्मक रही । इससे सीमा–विवाद सुलझाने के लिए प्रभावशाली तथा सक्रिय आधार बना । 1988 की यात्रा ने भारत तथा चीन के बीच उच्चस्तरीय सम्पर्कों की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया गया । नवम्बर 1989 से जून 1991 तक जनता दल के शासन के दौरान बिजिंग में राजीव गांधी द्वारा आरम्भ की गई प्रक्रिया को बनाए रखने का प्रयत्न किया गया। जून 1992 में राष्ट्रपति आर० वैंकटरमन व बाद में रक्षा मंत्री शरद पवार ने चीन की यात्रा (बीजिंग) की । इन यात्राओं, संयुक्त कमीशन की बैठकों, संयुक्त संचालन समूह की कार्यावाईयों ने भारत तथा चीन के संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय रूप में बनाए रखा । 1992 ई० में भारत में चीन उत्सव लगाया गया तथा 1994 में चीन में भारत का उत्सव लगाया गया । ये सभी तत्व भारत तथा चीन के बीच सम्बन्धों में सुखद नई प्रवृत्तियों की तरफ इशारा करने लगे । भारत चीन सम्बन्धों में उस समय नया मोड़ आया जब 29 नवम्बर 1996 को चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन भारत की तीन दिन की यात्रा पर आए और भारत की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया । दोनों देशों में अनेक समझौते पर हस्ताक्षर हुए । समझौते में हांगकांग पर चीन के अधिपत्य के पश्चात् यहां स्थित भारतीय दूतावास को कायम रखने, मादक द्रव्यों के व्यापार को रोकने, सीमाओं पर आपसी विश्वास बढ़ाने आदि पर समझौता हुआ । भारत व चीन का दो तरफ व्यापार पिछले पांच सालों में 20 करोड़ डालर से बढ़कर 1 अरब 20 करोड डालर हो गया । इसी कड़ी में 14 जून, 1999 को भारत के विदेश मन्त्री जसवन्त सिंह ने चीन की यात्रा की और बिजिंग में चीन के प्रधानमंत्री झिरोग्गी एवं विदेश मंत्री तांग जियासुआम से वार्ता की । चीन के खेल मंत्री बूसाजू की 16 से 18 दिसम्बर 1997 तक की यात्रा और जनवरी 1998 में चीन के परिवार कल्याण विभाग के सचिव की यात्रा से कार्यात्मक आदान–प्रदान जारी रहे। इसके साथ–साथ सैन्य सहयोग की तरफ भी दोनों देश अग्रसर रहे । जुलाई 2003 में भारत व चीन की पहली बार संयुक्त नौ–सैनिक अभ्यास किया । राजनैतिक रूप से तो दोनों देश एक दूसरे की निकट आ रहे हैं। भारत चीन दोनों ही भारत–चीन–रूस त्रिपक्षीय सहयोग की तरफ अग्रसर हैं । अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवाद पर अंकुश लगाने हेतु दोनों ही भारत–चीन–रूस त्रिपक्षीय सहयोग ही तरफ अग्रसर हैं । अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवाद पर अंकुश लगाने हेतु भी दोनों देश

एकमत है । 13 दिसम्बर 2001 को भारतीय संसद पर हुए हमले की चीन ने खुलकर निंदा की तथा दोनों देशों ने आंतकवाद का खात्मा करने का वचन भी किया । वर्ष 2010 तक भारत चीन सम्बन्ध एक दूसरे के प्रति शांतिपूर्वक, सद्भावना दिखाने का प्रतीकात्मक बिन्दु रहे हैं ।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अब चीन व भारत के बीच शान्तिपूर्ण वातावरण बनता जा रहा है । यही कारण है कि चीन के नेता भारत यात्रा पर और भारत के नेता चीन की यात्रा पर बार–बार आ जा रहे हैं । अब भारत व चीन में सांस्कृतिक, शैक्षिक, व्यापारिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ता जा रहा है । चीने ने भी यह भली भांति समझ लिया है कि भारत से मित्रता उसके लिए लाभदायक हैं । उसके दुश्मनी करना हानिकारक ही नहीं अपितु सर्वनाश की तरफ अग्रसर होना है।

सन्दर्भित पुस्तकें

1. मथुरा लाल शर्मा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, दिल्ली, 2008, पृ॰ 30 ।
2. यू॰आर॰घई॰, भारतीय विदेश, नीति, बम्बई, 2005, पृ॰155 ।
3. बी॰ए॰, स्मिथ, दा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कलेरेन्डन प्रैस, 1904, पृ॰ 356–358 ।
4. दया प्रकाश रस्तौगी, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, दिल्ली, 1996, पृ॰ 120 ।
5. पुष्पेश पंत, भारत की विदेश नीति, 1990, दिल्ली, पृ॰ 140 ।
6. भावना पोखरन, इंडिया चीन विश्लेषण, नई दिल्ली, 2009, पृ॰ 22।
7. मोहन मलिक, इंडिया चीन रिलेशन, 2004, पृ॰ 100 ।
8. एच॰सी॰सिंह, रिलेशन पिटबिन इंडिया एडं चीन फ्रांस असैम्बली एशियाटिक टू मॉर्डन टाईम्स, पृ॰ 95।
9. अभिनती भट्टाचार्य, सिक्टो ईयर ऑफ इंडिया चीन रिलेशं, ऑन लाईन प्रकाशन, 2016